Loans by Nationalised Banks to Weaker Sections of Socity visa-vis big Industrial Houses

7363. SHRIMATI KISHORI SINHA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state the position with regard to the lending position of nationalised banks to weaker sections of the society vis-a-vis the big industrial Houses?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAI BAROT): Advances to weaker sections, including advances under the Differential Rate of Interest Scheme are covered under Priority Sector which comprises of Agriculture, Small Scale Industry, Transport Operators, Retail Trade and Small Business, Professional and Self-Employed and Education.

The latest available comparative position of total advances, advances to Priority Sector, advances under D.R.I. Scheme and advances to large Industrial Groups (registered under Section 26 of Monopoly and Restrictive Trade Practices Act) as regards public sector banks, is as follows:

Advances	Rs. in crores
1. Total Advances*	17,287.00
2. Priority Sector*	6,006.53
3. D.R.I.*	139.49
4. Large Industrial Goups (As at the end of December, 1978)	1,442.08

*As at the end of December, 1977—Provisional.

ग्वालियर में फर्मों को इस्पात की सप्लाई

7364. **श्री दिलीप सिंह भूरिया:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1977 से 1979 तक स्टील यार्ड से ग्वालियर जिले की प्रत्येक फर्म को इस्पात की कितनी मात्रा सप्लाई की गई थी;

(ख) क्या उक्त फर्मों ने इस्पात का उसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया है, जिस प्रयोजन से उन्हें यह सप्लाई किया गया था;

(ग) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्होंने इस्पात के उस कोटे का उपयुक्त उपयोग नहीं किया है जो उन्हें सप्लाई किया गया था;

(घ) इस सम्बन्ध में हुई जांच में कौन-कौन सी फर्में दोषी पाई गई हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) स्टाकयार्ड से की गई सप्लाई का जिलावार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ख) प्रत्येक प्राप्तकर्ता के द्वारा किये गये इस्पात के उपयोग की जांच नहीं की जाती है। इस्पात के दुरुपयोग के जो विशेष मामले लोहा और इस्पात नियंत्रक के ध्यान में लाये जाते हैं उनकी जांच की जाती है। कुछ निरीक्षण अचानक और आकस्मिक भी किये जाते हैं।

(ग) से (ङ). दिसम्बर, 1970 में क्षेत्रीय लोहा और इस्पात नियंत्रक, हैदराबाद को इस्पात के दुरुपयोग के कुछ मामलों की रिपोर्ट मिली थी। जांच के आधार पर 11 इकाइयों के विरुद्ध इस्पात के दुरुपयोग के मामले सिद्ध हो गये थे। इन इकाइयों के नाम नीचे दिये गये हैं। इन इकाइयों को उनके नाम के सामने दी गई अवधि के लिए इस्पात की सप्लाई से विवर्जित कर दिया गया है। 6 और इकाइयों के विरुद्ध जांच का कार्य चल रहा है।

क्रम सं0	इकाई का नाम	विवर्जन की अवधि
1	2	3
1.	मेसर्स बाल्कीमल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लस्कर, ग्वालियर ।	2 वर्ष
2.	मेसर्स धर्म मैन्युफक्चरिंग कंपनी, लस्कर, ग्वालियर	2 वर्ष
3.	मेसर्स जेबी इंडस्ट्रीज, ग्वालियर	2 वर्ष
4.	मेसर्स एच० एच० जुनेजा कारपोरेशन, लोहिया बाजार, लस्कर, ग्वालियर ।	2 वर्ष
5.	मेसर्स बनमोर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, लोहिया बाजार, लस्कर, ग्वालियर ।	2 वर्ष
6.	मेसर्स संतोष आयरन इंडस्ट्रीज, दाबरा	2 वर्ष
7.	मेसर्स एस० एन० कंपनी, इन्डस्ट्रियल एस्टेट, ग्वालियर ।	2 वर्ष
8.	मेसर्स भोलानाथ संतोष कुमार जैन, लोहिया बाजार, ग्वालियर लियर ।	1 वर्ष
9.	मेसर्स संतोष एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज, ग्वालियर ।	1 वर्ष
10.	मेसर्स इंडियन आटो इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रिअल एस्टेट, ग्वालियर ।	2 वर्ष
11.	मेसर्स मास्टर इंजीनियरिंग वर्क्स, इंडस्ट्रिअल एस्टेट, ग्वालियर ।	1 वर्ष

Foreign Bank Accounts of Exporters of Diamonds and Precious Stones

7365. SHRI K. A. RAJAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that most of the exporters dealing with the exports of diamonds, precious stones and semi-precious stones are maintaining bank accounts in foreign countries to keep their funds received abroad over and above the value of the official invoice; and

(b) if so, the names of those exporters and the extent of the deposits in their accounts in foreign banks?

THE DEPUTY-MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAI BAROT): (a) and (b). Information regarding the exporters of diamonds, precious stones and semi-precious stones who were found to have been maintaining bank accounts in foreign countries in contravention of the provisions of the Foreign Exchange Regulation Act and to whom Show Cause Notices for the same were issued, or in respect of whom penal action was taken, by the Directorate of Enforcement, during the lost three years ending 30th June, 1980, is being collected and will be laid on the Table of the House.

Demand for Indian Opium in foreign markets

7366. SHRI ZAINUL BASHER: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that demand for Indian opium is decreasing in foreign market;

(b) if so, what are the causes; and

(c) what action Government are going to take for the increase in demand of Indian opium in foreign markets?